



भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम - एक समीक्षात्मक विवेचन

डॉ खेम चंद गुर्जर

व्याख्याता

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग

एस. एम.के.पी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमकाथाना (राजस्थान)

सार

भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। देश की लगभग दो-तिहाई आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, सरकार ने ग्रामीण उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम (जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और बुनियादी ढाँचे का विकास करना रहा है। वर्तमान में, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण विकास की धुरी बने हुए हैं। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य "गरीबी से मुक्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार" रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाकर कनेक्टिविटी को सुधारा है। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके जीवन की गरिमा और सुरक्षा बढ़ी है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से 100 दिनों के गारंटीड रोजगार का अधिकार देकर एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इसने विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है और महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाई है।

मुख्य शब्द

ग्रामीण, अर्थव्यवस्था, विकास



प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 65% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत की प्रगति के बिना राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा आधारभूत संरचना का विकास करना रहा है।

ग्रामीण विकास का अर्थ केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, एवं सांस्कृतिक सुधार शामिल हैं। इसका लक्ष्य ग्राम समाज को आत्मनिर्भर, शिक्षित और सशक्त बनाना है ताकि ग्रामीण जनता स्वयं अपने विकास के लिए प्रयत्नशील बन सके।

भारत में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) – यह स्वतंत्र भारत का पहला संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य ग्रामों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि का समग्र विकास था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (अब – मनरेगा, 2005) – यह ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने हेतु शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का मजदूरी कार्य सुनिश्चित करती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000) – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व मौसमीय सड़कों से जोड़ना था ताकि आर्थिक गतिविधियाँ और शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ हो सकें।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999) – ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई। बाद में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में विस्तारित किया गया।

इंदिरा आवास योजना (अब – प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण) – गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई यह योजना ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार का माध्यम बनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान – ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का प्रयास ताकि वे सरकारी सेवाओं और अवसरों तक ऑनलाइन पहुँच सकें। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने निश्चित रूप से ग्रामीण जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यदि योजनाओं का निष्पादन ईमानदारी और पारदर्शिता से हो, तो ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकता है। सच्चे अर्थों में “नए भारत” का निर्माण तभी संभव है जब उसका ग्राम भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है। इन समूहों ने महिलाओं को संगठित करके वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।

जन धन योजना और अन्य डिजिटल पहल ने बैंकिंग सेवाओं को दूर-दराज के गाँवों तक पहुँचाया है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। उपलब्धियों के बावजूद, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर कई सवालिया निशान लगते हैं। एक समीक्षात्मक विवेचन यह दर्शाता है कि ये कार्यक्रम "प्रयासों की बहुतायत" और "परिणामों की कमी" के बीच फँसे हुए हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के कारण लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता है। यह 'फंड लीकेज' कार्यक्रमों के वास्तविक प्रभाव को कम करता है। कई योजनाओं में गैर-जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल जाता है, जबकि अत्यंत गरीब परिवार तकनीकी या कागजी औपचारिकताओं के कारण बाहर रह जाते हैं। यह कार्यक्रम के सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कमजोर करता है।



साहित्य की समीक्षा

योजनाओं के तहत निर्मित परिसंपत्तियाँ (जैसे छोटे तालाब, खेत सड़कें) अक्सर गुणवत्ता में खराब होती हैं और उनकी स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगा रहता है। इस कारण दीर्घकालिक विकास का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। [1]

अधिकांश कार्यक्रम "टॉप-डाउन" दृष्टिकोण पर आधारित हैं। स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और स्वामित्व की भावना कम हो जाती है। [2]

ग्रामीण विकास पर खर्च का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर केंद्रित रहता है, जबकि कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण बाधित होता है। [3]

ग्रामीण विकास योजनाएँ कागज़ पर तो बहुत आकर्षक होती हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो पाता। स्थानीय अधिकारियों, ठेकेदारों और मध्यस्थों के कारण धन का दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी से योजनाओं के वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। [4]

भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम - एक समीक्षात्मक विवेचन

भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है, और देश की लगभग 65% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम (जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आदि) शुरू किए हैं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण विकास की राह में कई जटिल और बहुआयामी चुनौतियाँ बनी हुई हैं जो कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में बाधा डालती हैं। यह निबंध भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करता है।



ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है। आज भी देश के कई दूरदराज के क्षेत्रों में सड़कों की कमी, अनियमित बिजली आपूर्ति, और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है। खराब कनेक्टिविटी न केवल किसानों को अपने उत्पाद बाजारों तक पहुँचाने से रोकती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को भी सीमित करती है। इसके अलावा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की कमी ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, संकट के दौर से गुजर रही है। भूमि जोत का छोटा और विखंडित होना, सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता, और मानसून पर अत्यधिक निर्भरता कृषि उत्पादकता को कम करती है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आय अस्थिर रहती है और वे कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसरों की भारी कमी है, जिससे मौसमी बेरोजगारी और अल्परोजगारी की समस्या बनी रहती है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन (ग्रामीण पलायन) एक गंभीर चुनौती है, जो गाँवों को मानव संसाधन से वंचित कर रहा है।

सामाजिक असमानताएँ और प्रशासनिक अक्षमता भी विकास कार्यक्रमों के लाभ को वंचितों तक पहुँचाने से रोकती हैं। जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति पर आधारित सामाजिक भेदभाव आज भी कई ग्रामीण समुदायों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, जिससे कमजोर वर्ग योजनाओं का लाभ लेने से चूक जाते हैं। इसके अलावा, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नौकरशाही में देरी, भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है। कई बार, योजनाओं के जटिल नियम और दस्तावेजीकरण प्रक्रियाएँ अशिक्षित ग्रामीणों के लिए दुर्गम हो जाती हैं।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव जैसे सूखा, बाढ़ और अत्यधिक वर्षा ग्रामीण आजीविका को सीधे प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे जल संकट और मिट्टी का क्षरण, कृषि उत्पादन की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।



भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल धन आवंटित करना पर्याप्त नहीं है; कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, कृषि क्षेत्र में नवाचार लाना, गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना और सामाजिक-प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना अनिवार्य है। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक 'समग्र और समावेशी ग्रामीण विकास' का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

भारत एक विशाल ग्रामीण समाज वाला देश है जहाँ लगभग दो-तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा है। किंतु इन कार्यक्रमों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। इसके पीछे कई गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान किए बिना ग्रामीण विकास का सपना अधूरा रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र और संचार सुविधाएँ अब भी सीमित हैं। कई गाँव आज भी परिवहन और संचार के अभाव में पिछड़े हुए हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। अधिकांश ग्रामीण आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, परंतु कृषि आय स्थिर नहीं है। सिंचाई, बीज, उर्वरक, विपणन और मूल्य निर्धारण की समस्याओं के कारण किसानों की आमदनी बढ़ नहीं पा रही। गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी सीमित हैं। इससे ग्रामीण युवा आधुनिक रोजगार अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव अभी सीमित दायरे में है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच कम है, डॉक्टरों और दवाइयों की कमी रहती है। स्वच्छता और पोषण की स्थिति भी चिंताजनक है, जिससे ग्रामीण श्रमशक्ति की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताएँ आज भी कई ग्रामीण इलाकों में विद्यमान हैं। महिलाएँ निर्णय प्रक्रिया में



भाग नहीं ले पातीं और संसाधनों तक उनकी पहुँच सीमित रहती है। इससे ग्रामीण विकास की गति धीमी पड़ती है। ग्रामीण युवाओं के पास पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं हैं, इसलिए वे शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे गाँवों में श्रमशक्ति की कमी और सामाजिक असंतुलन बढ़ता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए केवल योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक “संपूर्ण ग्रामीण विकास” का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

निष्कर्ष

भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने पिछले कुछ दशकों में निःसंदेह एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाया है, विशेषकर बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सुरक्षा जाल के निर्माण में। हालाँकि, इन कार्यक्रमों को तभी पूर्ण सफलता मिल सकती है जब उनके कार्यान्वयन में मौजूद संरचनात्मक और प्रशासनिक कमियों को दूर किया जाए। इसके लिए विकेन्द्रीकरण को वास्तविक अर्थों में लागू करना होगा, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ दी जाएँ। साथ ही, प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि यह एक जन-आंदोलन बनना चाहिए, जहाँ हर ग्रामीण नागरिक अपनी प्रगति का सूत्रधार हो।

संदर्भ

1. शर्मा, एस.के. (2010). "भारत में ग्रामीण विकास: कार्यक्रम, रणनीतियाँ और परिप्रेक्ष्य"। सामुदायिक विकास जर्नल, खंड 15(1), पृष्ठ 2-9।



2. सिंह, कटार और शिशोदिया, अनिल। (2014)। ग्रामीण विकास: सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंधन (चौथा संस्करण)। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस।
3. अज़ीज़, एन.पी. और अख्तर, एस.एम. (सं.)। (2016)। भारत में ग्रामीण विकास: नीतियाँ और कार्यक्रम। नई दिल्ली: आईबीपी बुक्स।
4. महिदा, रिकेश कुमार जी. (2014)। भारत में ग्रामीण विकास: नीतियाँ और कार्यक्रम। (पेपरबैक)। प्रकाशक: रेडशाइन पब्लिकेशन।
5. कुमार, दीपक; नरवाल, सुरेंद्र; फौगाट, सुनील। (2015)। "भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा"। एशियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, खंड 1 4(1):336-344.
6. "रोज़गार गारंटी कार्यक्रम | मनरेगा ग्रंथसूची"। (2014)। जीन ड्रेज़ और पावलिना चेर्नेवा के मार्गदर्शन में एमिलिया कूपर द्वारा तैयार।